



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई0

माघ 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 141/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5

देहरादून, 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर से उस सीमा तक छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिस सीमा तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्रीय सरकार के हिस्से, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्रीय सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.141/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5, dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 141/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-5
Dated Dehradun, February 06, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to exempt the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the State tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as laid down in the contract made by the Central Government for this purpose.

2. This notification shall deemed to come into force from the 25th day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.